Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 14-03-2006

Participants : Patle Shri Shishupal Natthu,Verma Shri Bhanu Pratap Singh,Pradhan Shri Ashok Kumar,Pawar Shri Sharad Chandra Govindrao,Khanna Shri Avinash Rai,Acharya Shri Prasanna,Vijayan Shri A.K.S.,Jai Parkash Shri ,Joshi Shri Prahlad,Seal Shri Sudhangshu,Gudhe Shri Anantrao,Kumar Shri Shailendra,Mahato Shri Bir Sing,Pandey Dr. Laxminarayan,Senthil Dr. R,Saroj Shri Tufani,Kathiria Dr. Vallabhbhai,Thummar Shri Virjibhai,Bhargav Shri Girdhari Lal,Yerrannaidu Shri Kinjarapu,Singh Shri Bijendra,Munshiram Shri ,Yadav Shri Baleshwar,Patil Shri Balasaheb Vikhe,Prasad Shri Lal Mani,Gandhi Smt. Maneka,Radhakrishnan Shri Varkala,Jalappa Shri R.L.,Meinya Dr. Thokchom,Pradhan Shri Dharmendra,Singh Shri Sitaram,Ajnala Dr. Rattan Singh,Kripalani Shri Srichand,Gowda Dr. (Smt.) Tejasvini,Shivanna Shri M,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Yadav Prof. Ram Gopal,Chandrappan Shri C.K.,Manoj Dr. K.S.,Ravichandran Shri A.,Reddy Shri Mekapati Rajamohan,Wangyuh Shri W.

>

Title : General Discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture (All the cut motions moved were negatived).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take discussion and voting on Demand Nos.1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put on the Notice Board shortly thereafter. In case, any hon. Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Dr. Vallabhbhai Kathiria.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार बजे तक का समय दिया गया है। क्या यह कृषि के साथ अन्याय नहीं होगा? इस पर डिबेट होगी और दो ही घंटे में ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : जीरो ऑवर के लिए हम कभी नहीं रोकते हैं। सभी पार्टियों ने आज बैठकर इसको तय किया है। इसलिए इसके बारे में बात मत कीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान[c36])

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record, Mr. Bhargava.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

---

*Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कल होली है और सब को जाना है। उनके लिए भी प्रॉबलम होगी। बोलने वाले भी शायद कम होंगे। इसलिए फैसला किया गया है कि जीरो आवर आज नहीं हो।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः होली के कारण सब को घर जाना है इसलिए सभी चाहते हैं कि जीरो आवर न हो।

There is no 'Zero Hour' today.

Now, I would request the hon. Member, Dr. Kathiria to initiate the debate.

I am sorry, I had forgotten one thing that अगर ऑनरेबल मैम्बर्स अपनी रिटर्न स्पीच ले करना चाहते हैं तो ले कर दें। हम उनको धन्यवाद करेंगे।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कल होली है इसलिए बहुत से लोगों ने जाना है

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved :

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolitaded Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture. "

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट 2006-07 की कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 68 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। प्राचीन काल से कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का आधार कृषि है। जब भीम पितामह युधिटिर को राजधर्म सिखाने् गए थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य में कोई किसान पीड़ित तो नहीं हैं और जो समाज का पूरा बोझ उठा रहा है, उस किसान का क्या आप ख्याल रखते हैं? पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सभी का जीवन-यापन कृषि के कारण होता है। उनके प्रति आप सजग हैं या नहीं? क्या आपके राज्य में पर्याप्त मात्रा में तालाब की व्यवस्था है? अगर तालाब हैं तो उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार है या नहीं? यदि सूखे की अवस्था है तो उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? ऐसे बहुत से प्रश्न उस समय भी उठाए जाते थे। इस प्र ाकार कृषि को महत्व दिया गया था।

पूरी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और 68 परसैंट आबादी कृषि पर निर्भर है। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय दो पहलू रखे। उन्होंने किसानों के लिए अच्छी बात कही है। मैं उनको धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए ऋण की ब्याज दर जो 7 परसैंट की है, उसके लिए भी उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले साल एक लाख रुपए के नीचे जितना ऋण था, उसके लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन दो बातों के लिए कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं। कृषि विभाग के साथ कनैक्टिड वाटर रिसोर्सिज. फूड प्रोसैसिंग आदि विभाग हैं लेकिन इनके मंत्रालय अलग-अलग हैं। मेरा मानना है कि उसमें कृषि विभाग, कृषि का वित्त विभाग, कृषि संलग्न विभाग, कृषि कानून विभाग और कृषि के तहत अन्य विभाग रहें। एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज, वैल्यू एडिशन के लिए एग्रो प्रोसैसिंग, एनिमल हजबैंडरी, कोआपरेटिव्स, बायो टैक्नॉलोजी आदि को एक कर दिया जाए। यहां अलग-अलग कई तरह की स्कीम्स आती cé[R37]।

उन स्कीम्स के लिए एक डिपार्टमेंट क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है, उनका बंटवारा नहीं होता है जिससे अच्छी तरह से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि सारी स्कीम्स को कन्वर्ज करके एक डिपार्टमेंट और एक मिनिस्ट्री के अधीन लाने की आ वश्यकता है।

13.36 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

अब मैं बजट के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। मैं सबसे पहले कृषि के बारे में कुछ लिखा गया है, उससे शुरू करूंगा - कृषि यज्ञ है, कृषि एक धर्म है, कृषि कला है, कृषि विज्ञान है, कृषि कर्मयोग है, कृषि स्वाध्याय है, कृषि राट्र की रक्षा है, कृषि ऋषि कार्य है, कृषि प्रकृति की पूजा है, कृषि प्रकृति का दोहन है, कृषि मातृभूमि की सेवा है, कृषि सर्वजीव का योगक्षेम है, कृषि मांसाहार का विकल्प है, कृषि स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय है, कृाक प्रकृति का पुजारी है और पर्यावरण का रक्षक है, कृषि भगवान की पूजा है, कृषि सेवा है, कृषि आराधना है और कृाक उसका पुजारी है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद कृषि को जो महत्व देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। मैं आंकड़ों के साथ पुटि करते हुए कहना चाहता हूं कि देश की 68 परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है फिर भी जी.डी.पी. में 25 परसेंट का ही योगदान है, जबकि पिछली आठवीं, नौंवीं और दसवीं योजना के पिछले पन्द्रह साल के आंकड़ें देखें तो आज तक कृषि पर इन्वेस्टमेंट 1.3 परसेंट है, कृषि में निवेश हुआ है। जबकि योगदान 25 परसेंट है लेकिन केवल 1.3 परसेंट इन्वेस्टमेंट वो भी निजी क्षेत्र के साथ हुआ है। यदि निजी क्षेत्र को छोड़ दें तो 0.3 परसेंट ही सरकार द्वारा किया गया है। मुझे लगता है यह बहुत कम है जबकि 68 परसेंट कृषि पर निर्भर हैं और रोजगार के रूप में 56.3 परसेंट मिलता है।,

कृषि का जी.डी.पी. में योगदान देखकर यदि कृषि में निवेश की चर्चा करें तो 1.3 परसेंट के बजाय बजट का 7 परसेंट कृषि को मिलना चाहिए। यदि रोजगार की बात करें तो 16 से 17 परसेंट निवेश कृषि में होना चाहिए। यदि डिपेंडेंसी रेश्यो देखें तो 21 से 22 परसेंट इन्वेस्टमेंट कृषि में होना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन्क्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेश्यो जिसका मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों का आउटपुट यानी सामान्य शब्दों में जितनी पूंजी किसी भी व्यवसाय में लगाएं उसका पूरा रिटर्न कब मिल सकता है। उदारहण के तौर पर यदि किसी ने एक लाख किसी बिजनेस में लगाया है तो उसका पूरा रिटर्न यानि एक लाख कब मिलेगा। इसके आंकड़े दिये गये है कि यदि रुपया उद्योग में लगाएं तो 7.77 यानी पौने आठ साल में वापिस मिलता है, यदि संचार व्यवस्था में पूंजी लगाएं तो 8.33 वर्ा में, यदि सड़क और परिवहन में लगाएं तो 5.37 वर्ा में, यदि माइनिंग में लगाएं तो 7.99 यानि आठ साल में, यदि रेलवे में लगाएं तो 14.66 साल में, यदि बिजली क्षेत्र में लगाएं तो 15 साल में रिटर्न वापिस मिलता है। लेकिन जब खेती में पूंजी लगाते हैं, इसके लिए कहा गया है

कि 1.99 यानी दो साल से भी कम समय में खेती का पूरा रिटर्न मिलता है। मुझे लगता है कि खेती की उपेक्षा की गई है, आजादी के 58 सालों के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सबसे ज्यादा फायदा और रोजगार खेती से मिलता है, और इसके कारण गरीबी उन्मूलन जल्दी हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से खास तौर से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बजट और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कृषि में करें और कृषि के लिए अलग बजट का प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए मैं विनती करता हूं।

दूसरी बात मैं किसानों के बारे कहना चाहता हूं कि पिछले पचास सालों में किसानों की जो लागत लगती है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। लेकिन किसानों को जो उनकी उपज का प्राइस मिलता है, वह घट गया है। जिसके कारण आज स्थिति ये है कि 78 परसैन्ट खेती प्रोफिटलैस है। यानी कि किसान माइनस में हैं। लगभग 78 परसैन्ट किसान घाटे में चल रहे हैं। केवल 1.6 परसैन्ट किसान लाभकारी खेती करते हैं। जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा जमीन है, वही किसान लाभ में हैं। बाकी के लोग बीच में हैं, जिन्हें न लाभ होता है और न नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि अभी 78 परसैन्ट किसानों को खेती से नुकसान हो रहा है। इसके बारे में हमें विचार करके खेती के लिए सरकार को विशेा प्रबंध करने की आवश्यकता है अलग बजट प्रस्तुत करना चाहिए।

सभापति महोदय, यदि हम प्लान आउटले की बात करें तो योजना आयोग के अंतर्गत प्लान आउटले में खेती के लिए 4.5 परसैन्ट दिया गया है, जबकि यह 25 परसैन्ट देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जी.डी.पी. का परसैन्टेज है, उसके अनुपात में यहां 4.5 परसैन्ट दिया गया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल खेती को जो महत्व देना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। सब बाते करते हैं, आप बॉयोटैक्नोलोजी का प्रचार कर रहे हैं। जेनेटिक मोडिफिकेशन के लाभ किसानों की समझ में आ रहे हैं और इनके कारण उत्पादन भी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारी चिंता यह है कि पिछले सालों में उत्पादकता और कुल उत्पादन स्टैगनैन्ट हो गया है, वह बढ़ नहीं रहा है। उसका कारण यह है कि हम फर्टिलाइजर का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। चूंकि फर्टिलाइजर देने के बाद अधिक पानी देने की जरूरत होती है। हमें सोचना चाहिए कि बॉयोटैक्नोलोजी का उपयोग करके, फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करके उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड .योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, जो बहुत लोकप्रिय रही है।

MR. CHAIRMAN : We have very limited time. Several hon. Members from your Party have given their names to speak.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : सर, मैं पहला मैम्बर बोल रहा हूं। मैं सारे किसानों के फायदे की बात कर रहा हूं। किसान क्रैडिट कार्ड से किसानों को बहुत फायदा हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : सर, मैं फिगर्स बता रहा हूं, इनसे पूरे देश को फायदा होगा। अभी किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई, किसान क्रेडिट कार्ड से अभी तक 5 करोड़ और 56 लाख किसानों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम वर्ा 2007 तक सारे किसानों को क्रेडिट काड्र्स दे देंगे। लेकिन बजट में जो प्रोविजन किया गया है, उसे देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दे देंगे और इस काम को 2007 तक खत्म कर देंगे।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा स्वरोजगार का है। आप जानते हैं कि गुजरात सरकार ने एक बड़ा ही अभिनव प्रयोग किया है। सभी किसानों के लिए हमने पिछले साल कृषि रथयात्रा निकाली, कृषि महोत्सव किये। पूरे गुजरात के 18 हजार गांवों में कृषि रथ गये। लगभग दो हजार से ज्यादा साइंटिस्ट्स लैब से लैन्ड तक गये। यानी जो लैबोरेटरीज में काम करते हैं, वे लैंड तक पहुंचे और उन्होंने वहां कृषि के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, ड्रिप स्प्रिंकलर, बॉयो-फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग आदि वियों के बारे में किसानों को जानकारियां दीं। मेरा मानना है कि जिस तरह से जल्दी से जल्दी पूरे देश में किसानों को क्रेडिट काड्र्स दिये गये हैं, वैसे ही अन्य सुविधाएं भी देने की आ वश्यकता है।

मेरा अगली बात फर्टिलाइजर के बारे में हैं। 1965 के बाद हमारे देश में हरित क्रांति हुई। लेकिन उसमें फर्टिलाइजर का रोल ज्यादा रहा। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो पता चलता है कि फर्टिलाइजर से जितना फायदा हो रहा था, अब वह स्टैगनैन्ट हो गया है। अब इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। चाहे वह आरोग्य की दृटि से हो या अन्य किसी और दृटि से हो। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का जमाना आ गया है, जिसमें वर्मी कल्चर के द्वारा, गाय के गोबर के द्वारा खाद बन सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 29 करोड़ कैटल पापुलेशन है और इस कैटल पापुलेशन का जो गोबर होता है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो उसके कारण हमें जितना कम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर मिलेगा, उससे काफी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर और कैमिकल्स के उपयोग की मात्रा कम करके गोबर की खाद से अपना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि देश में "कैटल वैल्थ पालिसी" बनाने की बहुत आवश्यकता है।

वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में गुजरात ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाटर हार्वेस्टिंग के कारण वहां किसानों को जो फायदा हुआ है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोरबीशहर में पिछली दीवाली को एक ही दिन में एक हजार हीरो होंडा का ऑर्डर मिला[R38]।

वाटर हारवेस्टिंग के कारण किसानों की फसल की ज्यादा पैदावार हुई और किसान समृद्ध बने। जैसे मैंने पहले कहा कि कृषि में इनवेस्टमेंट में दो साल में पूरा रिटर्न मिलता है और उसमें अगर आगे बढ़ें तो चेक डेम से माइक्रो इरीगेशन से आठ महीने में ही रिटर्न मिल जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बजट और इनवेस्टमेंट इसी में ही करना चाहिए ताकि हमारा जीडीपी बढ़े। जहां पानी ज्यादा है, वहां से सूखे प्रदेश में रीवर लिंकिंग करके पानी दिया जाए। जहां वर्षा होती है, वहां वर्षा के पानी को इकट्ठा करके हारवेस्ट किया जाए ताकि किसानों को उससे फायदा हो।

महोदय, पेस्टीसाइड और फर्टिलाइज़र बंद करके आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मार्केटिंग की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को ठीक से दाम मिलें, क्योंकि हमारे देश में छोटे-छोटे किसान हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हरबल प्लांट्स, ऐसी अलग-अलग पैदाइश का बढ़ावा करने और प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है। इनडिजिनेस मशीनरी, जो किसान को खेत और हारवेस्टिंग में उपयोग में आती है, इसके लिए उन्हें सब्सिड़ी देकर प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय, मंडी में ऐसे कम्प्यूटर्स की व्यवस्था करें ताकि उससे किसानों को बाजार की और कृषि की सारी जानकारी मिले। किसान को जो ब्याज की माफी की है, उन्हें जो वापस देना है, उसके लिए आपने 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह आपके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारा देश कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि को बड़े पैमाने पर सहायता देने की आवश्यकता है। गुजरात कृषि क्रांति में रोल मॉडल बना है। गुजरात की कृषि जीडीपी 11.1 परसैंट है, जिसे हम अगले साल 14 परसैंट तक ले जाने वाले हैं, जब कि देश की जीडीपी केवल 2.3 परसैंट है। गुजरात में जिस-जिस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, उसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह जो अच्छे-अच्छे काम हुए हैं, उनका कृषि नीति बनाने में उपयोग करना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are six more speakers from your Party. Please conclude now.

डा. वल्लभभाई कथीरिया : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, अगर किसानों का हाथ ढीला पड़ गया तो तपस्वियों का तप भी बेकार हो जाता है, यह बात थिरूवलूवर नाम के एक कवि ने कही है। अगर ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसानों के माध्यम से हमारी जीडीपी बढ़ेगी और देश का विकास होगा। इसलिए सबसे ज्यादा बजट और इनवेस्टमेंट कृषि में ही देने का प्रयास करना चहिए।

*Use of organic manual especially cow-dung and biofertilizer will increase the productivity with healthy produce and will help in positive health & less expenses.

- Subsidy on fertilizer should be given to farmers directly & not to fertilizer companies.
- Developed countries provide 44% subsidy on Agricultural Produce, while we provide only 6% subsidy.
- W.T.O. norms need not be forced to implement on farming-Agriculture.
- Interest rate to Agriculture credit should be reduced to 6% instead of 7% subsidy to be provided for minor irrigation drip and sprinkler system
- Kishan Channel should be telecast in the evening time for two hours at least.
- Organic farming for fruits, vegetables & medicinal plants in the demand of time, which requires more help by Govt.
- For "Shaswat Harit Kranti" it is high time to invest maximum in Agriculture Sector.
- The provision of withdrawal of exemption in IT under Section 80 (P) of IT Act 1961 of Urban Cooperative Bank should be reinstituted i.e.

---

* This part of the speech was laid on the Table.

there should not be any I.T. on Urban Co. Banks, which were passing through crisis.

- Cooperative contract farming should be enclosed instead of multinationals or corporate.
- Today, because of unseasonal rainfall, the majority of crops have failed.
- Corp Insurance in the form of comprehensive Agriculture Insurance Scheme requires to be implemented.
- Remunerative prices should be given to farmers.
- With drip and sprinkler the not irrigated area should be increased upto 100% from 40% at present with atleast two crops in a year.*

CUT MOTIONS

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

84. जैव कृषि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असफलता।

85. त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असफलता।

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृठ 1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

86. कृषि ऋणों पर ब्याज की दर घटाए जाने की आवश्यकता।

87. ओलावृटि द्वारा समय-समय पर होने वाले नुकसान को देखते हुए अन्य फसलों के अलावा फलों, फूलों और सब्जियों को भी फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

88. किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।

89. पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव में एक "किसान कॉल सेंटर " स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

90. जैव-कृषि उत्पादों को पैदा करने वाले किसानों, को विशेा अनुदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

91. वास्तविक जल मापन के आधार पर सिंचाई की पक्की नहरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृठ 2) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

92. ड्रिप सिंचाई के उन्नयन और उसे सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिक विकसित किए जाने की आवश्यकता।

93. उत्तरांचल के अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एक पर्वतीय बागबानी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

94. देश में माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर कृषि को एक अनिवार्य विाय बनाए जाने की आवश्यकता।

95. समूचे देश में प्रखंड स्तर पर किसानों के लिए प्रदर्शनी और प्रशिक्षण हेतु स्थायी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

96. देश के प्रत्येक गांव को बागबानी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता।

97. बीजों की उन्नत किस्में विकसित करने के लिए एक मिशन आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

कि पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृठ 3) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

98. गायों, भैसों, भेड़ों, बकरियों आदि की उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

99. उत्तरांचल के चंपावत जिले में नारीयाल गांव में भेड़ प्रजनन केन्द्र के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित की गई भूमि पर यह केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

100. उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के गुदलेख में स्थापित भेड़ प्रजनन केन्द्र में कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता।

101. उत्तरांचल के चम्पावत जिले में बनलेख में शीतल जल मत्स्य-पालन केन्द्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता।

102. डेरी स्थापित करने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किसानों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

103. गाय और भैंस की नस्लों में सुधार के लिए इम्ब्रायो अंतरण प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता।

104. उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में स्याल्दे विकास खंड में कुरमुल्ला कीट की समाप्ति के लिए प्रभावी कार्य किए जाने की आवश्यकता।

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली) : महोदय, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है जब तक गांवों में रहने वाले किसानों का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास के बारे में सोचना पागलपन होगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी जो किसानों की दशा को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें असली विकास की परख है उनकी अगुवायी में जो खेती बाड़ी के बारे में परिवर्तन के लिए सोचा है उससे हमारे किसानों की काया पलट होने का समय आया है।

दो सालों के दौरान किसानों के लिए जो लोन का लक्ष्य प्रापत हुआ है उससे लगता है कि हमारा कृाि विकास रास्ता सही चल रहा है और आने वाले साल में ऐतिहासिक 1 लाख 75 हजार करोड़ रूपया किसानों के लोन के लिए रखा है और किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जायेगा जो किसानों के हित में है, परन्तु सरकार से अनुरोध है कि विदेशी बैंक और निजी बैंकों को भी कृाि लोन देने के लिए नियम बनाया जाये, यह ठीक नहीं है कि मीठा मीठा विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र खाये और कड़वा हमारे सरकारी बैंक खाये। इस साल जो कृाि ऋण वितरण के प्रवाह में बढ़ोत्तरी है और पूर्व वर्ो की अपेक्षा इस वर्ा में ऋण प्रतिशत किसानों के लिए बढ़ा है जो प्रसन्नता की बात है और 50 लाख नये किसानों को ऋण दिया जायेगा यह भी यूपीए सरकार के लिए गर्व की बात है।

देश में प्राकृतिक आपदा की मार गत साल बहुत पड़ी है। महाराट्र, गुजरात, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में बरसात बहुत बड़ी मात्रा में हुयी है, जिससे किसानों की फसल बहुत मात्रा में खराब हुयी है। फिर भी चावल की पैदावार में दो प्रतिशत की बढोत्तरी हुयी है और गेंहू के उत्पादन में कमी आयी है, परन्तु असामयिक बरसात के बाद भी देश में गेहूं के उत्पादन खराब हुआ है आम की फॅसल भी खराब हुयी है और प्याज के उत्पादन अच्छी होने के बाद बैमौसम की बरसात से प्याज की फसल खराब हो गयी है। किसानों का गेहूं के आयात का प्रबल विरोध हो रहा है उस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए।

कृाि के विकास में 2.3 विकास दर को होना संतोा की बात है क्योंकि पहले के दो चार वर्ो का देखें तो हमारा कृाि उत्पादन सही नहीं रहा है। इससे पता लगता है कि यूपीए सरकार की नीति से किसान संतोा में हैं और विकास के रास्ते में अग्रसर हैं।

सरकार ने फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, परन्तु फसल बीमा योजना में राज्य सरकार और बैंक अपने उत्तरादायित्व को पूरा नहीं करती है और इसमें काफी फारमेलटीज है, जिसको किसान पूरा नहीं कर पाते हैं। इन फारमेलटीज को कम

किया जाना चाहिए।

---

* The speech was laid on the Table.

कई राज्यों में कपास की खेती पर कई लाख किसान के परिवार निर्भर है परन्तु उनको बी टी कॉटन के बीज नहीं मिल पाते हैं और कई जगह तो नकली बीज दिये गये जिसके कारण कपास के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है और कपास किसानों को उनकी मेहनत के बराबर प्रतिफल नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका समर्थन मूल्य लागत से कम मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देश के कपास किसानों को बीमा प्रीमियम के रूप में साढ़े चौदह प्रतिशत भरना पड़ता है और लोन का ग्यारह प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है एक लाख का लोन लेने किसान को साढ़े चौबीस हजार रूपया इन दोनों के रूप में चला जाता है और फसल खराब हो गयी तो आत्महत्या की ओर कपास किसान को जाना ही पड़ेगा। सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कॉटन बीमा प्रीमियम का ढाई या तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी किसानों को हम बचा पायेंगे।

देश में अभी कई क्षेत्रों के किसान बरसात के पानी से अपने खेत को सींचते हैं जिनके कारण अच्छी बरसात अगर हो गयी तो उनको फसल मिल पाती है। देश में 388 के करीब सिंचाई परियोजनायें लंबित हैं जो अपने निर्धारित समय में पूरी नहीं हुयी हैं। परन्तु, यूपीए सरकार ने इस वर्ा 4500 करोड़ रूपये की व्यवस्था करके त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिससे हमारी लंबित सिंचाइ परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। और इस बजट में 7121 करोड़ रूपये की व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए है। पहले सिंचाइ योजनायें की आधारशिला रखकर उन पर कछुए की चाल की तरह काम हो रहा था। परन्तु, इस साल से सिंचाई परियोजनाओं ने गति पकड़ी है। सरकार से यह भी अनुरोध है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और वॉटर शेड स्कीमों से नाहक देरी होती है उसमें तेजी लायी जाये।

इस सरकार ने कृाि के साथ बागवानी, पशुपालन और फूल उद्योग के लिए धनराशि की व्यवस्था की है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Budget and I welcome it. The current year's Budget has given a good relief to the farmers in some areas but it needs to have a re-look in a few areas as some difficulties need to be solved. I do agree that one year or two years' time is not sufficient for solving the entire problems of the agriculture or the farmers. One good thing here is that, the Plan outlay has been increased to Rs.6927 crore from Rs.5900 crore, which was reduced to Rs.5559 crore in the revised budget estimates. In the same way, the revised budget estimates of the Department of Consumer Affairs and the Department of Food Processing industries was Rs.213 crore, which has been increased to Rs.370 crore[r39].

This is a good beginning, but it further requires to be supplemented through subsidy. In the Budget papers I saw that subsidy has a declining trend. Subsidy though is not a good thing, yet there is no other alternative available at present. If the Government could come out with a new mechanism to support the farmers, other than by giving subsidy, then that would be good.

There has been a growth in agriculture from 1.1 per cent to 2.3 per cent. Production of food grains though has not touched a record level, yet there have been production of 209.3 million tonnes of food grains, which is five million tonnes more than last year. Around 60,000 hectares of land is proposed to be brought under irrigation through schemes like AIBP. There has been an increased outlay from an odd Rs.

4,000 crore to Rs. 7121 crore. Fifty per cent subsidy is proposed for drip irrigation and sprinkler irrigation for all big, small and marginal farmers, including farmers who belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities and even for women farmers. The Minister may consider giving 90 per cent subsidy to the small and marginal farmers and also for women farmers and farmers belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. It is because drip and sprinkler irrigation are expensive modes of irrigation.

Sir, in regard to making available credit to farmers I would, first of all, like to congratulate the hon. Prime Minister in particular and also as the present custodian of the Department of Agriculture and the person who once led the co-operative movement, Shri Sharad Pawar for proposing to increase credit limit three fold and announcing that the credit limit would now be Rs. 1,75,000. I must say, this is a good beginning. At the same time, the Government has announced a package of Rs. 1500 crore for strengthening the co-operative and the banking sector as a whole. But this allocation has been made under the Ministry of Finance and not under the Ministry of Agriculture. Similarly, there is also a proposal to give relief on interest. But that allocation also is under the Ministry of Finance and not under the Ministry of Agriculture. I would also like to congratulate the Government for reducing the interest rate to seven per cent on short-term loans from the coming *Kharif* season. This, in a sense, is a good beginning. As the hon. Minister is aware that small and marginal farmers require capital investment and these categories of farmers would have to sustain a high rate of interest on capital investment. Our appeal to the hon. Minister was to reduce the rate of interest to four per cent for the small, marginal and farmers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community and for women farmers. But it has now been reduced to seven per cent. My congratulations are also due to the Prime Minister for this.

The Common Minimum Programme of the UPA Government talked about strengthening and re-designing of the crop insurance scheme. But the Government has continued with the same crop insurance scheme. I would like to appeal to the Government to bring in an constitutional amendment to make necessary changes in order that the democratic and the autonomous character of the co-operatives are maintained. Apart from this I would also like to suggest that a comprehensive crop insurance scheme should be adopted. There are three types of insurance: One is the farm income insurance scheme for which the Budget allocation in the current year is zero. Two, Technical Insurance Scheme for which the Budget allocation in the current year is zero. Third, Agriculture income insurance Scheme budgeting provision is zero. But the need of the hour is to have a road map as was declared last year's budget. I would be grateful if the hon. Minister, in the course of his reply, would enlighten us as to what kind of a road map he is going to have for the current year so that we could have diversified and value added crops. Why I am talking about this is because import of agriculture products is growing and export is declining. There is no infrastructure for export, for agriculture. I know this subject is being dealt with the Commerce Ministry. There is requirement of one family doctor for total agriculture. We cannot have so many specialist doctors for one Department. We need to have a single window concept. Single Window concept should be introduced in the Ministry of Agriculture. In the corporate sector there is the concept of a single window. There should be a single window system in the Agriculture Ministry and other related Ministries can co-ordinate with it at the floor level as well as at the top level. This is my humble submission.

I know there are constraints. But I would like to congratulate the hon. Prime Minister for his efforts to improve the condition of the farm sector from the day he has taken over. There is a need for revival of the insurance scheme and various other schemes in the Ministry of Agriculture. I know the UPA Chairperson is concerned about all these aspects[snb40]. But the point [bru41]is, Rain-Fed Authority is not created. The Prime Minister has announced from the Red Fort on 15th August about it. Almost 65 per cent

of our country is rain-fed area and 40 per cent of our foodgrains are produced there. About nine million people are living in the rain-fed areas. The need of the hour is to create a Rain-Fed Authority. Why I am saying this is because the developed areas in the State is siphoning off the money as they have the capacity to absorb the funds. Rain-fed areas do not have the capacity to do so. Such areas should be monitored. Drought-prone areas, flood-prone areas and cyclone-prone areas are not developed. So, if the Rain-Fed Authority is created, then some problems can be solved.

Regarding research and development, I do not understand the provision given in the Budget. NABARD is to open a line of credit for financing farm production and other activities through self-help groups. Now, where is the professional knowledge? I can understand that if some Krishi Vigyan Kendras are attached to the self-help groups, then it can be worked out. Otherwise, today the banks there are not professionals in PLRs. Then how can these SHG be possible?

About national agricultural project of research, it is in the frontier of agricultural science since July, 2005. I am happy to note that there are three universities concerned with this area. An amount of Rs. 100 crore is given to the Ludhiana University. They have established Rajiv Gandhi Centre for Technology. There are three other universities which have been given Rs. 50 crore for this area. Even the Thanjavur Rice Research Centre will develop a full-fledged Rice Research Institute. There is a need for a hybrid Rice Research Institute. What about the position in China? About 5 million hectares come under paddy cultivation. What about our country? We are importing wheat and, the next time, we will import rice also. So, I would request the Government to kindly diversify research to hybrid and give assured good price, good technology and good seeds. Seed Bank was created. Now it is wound up. There was some expenditure incurred for two years and last year, there was nil expenditure in the current year. Quality seed is the need of the hour. There is a need for public and private participation for quality seeds because production of seeds is very expensive. So, there is a need for an intervention in this area by the state.

Regarding rural development, there is one point which I want to make. As far as rural roads are concerned, already Rs. 500 crores are allotted from the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, and CRF also is there. At the same time, for rural infrastructure, Rs. 4000 crores have been allotted by the RIDF for rural roads. There is a mention of this in the Budget. But that is not enough.

Coming to irrigation, without irrigation, how will the farmers work? Irrigation is a major area of concern so far as rural areas are concerned. These are the major issues which I would like to focus my attention on. I think the hon. Minister will look into these issues as he knows better than myself. He is a champion in these areas.

I would highlight some problems which we are facing. Agriculture is the only source of employment in villages. Without agricultural produce, no farm employment will be there. Sustainability of agriculture means rural economy must sustain. Government is now talking about Green Revolution. I want the Minister to convert Green Revolution into Ever Green Revolution and the Minister is capable of doing it. Only then, it will yield good results.

I think everybody would have gone through the Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan. They have given a note on this issue. There is a need to relook about the total strategy of agricultural policy. From 1990 onwards, that is, for the last 15 years, we find that there is a decline in investment in production[bru42].

14.00 hrs.

So[r43], there is a need for Government intervention and there is a need for reversing the policy. The Public investment is required. But the major thing is the intervention of the Government is a must.

As far as the irrigation is concerned, long-pending projects, which are pending for the last thirty or forty years should be taken up as national projects. In 1992-95, we had taken some projects as national projects. So, some irrigation projects should be taken as national projects because irrigation is the backbone of agriculture. Without irrigation, agriculture cannot be developed. Only islands are developed. The national average is 48 per cent as far as the irrigation is concerned. But what about Maharashtra? It is hardly 15 or 16 per cent. Some States are even below that. The need of the hour is to develop irrigation. I do understand that Ministry of Water Resources does not come under the Ministry of Agriculture. But there should be a family doctor. Who will look after the agriculture, if everybody says that agriculture does not come under his jurisdiction? Then, under whose jurisdiction will it come? The Government is the one. It is the collective responsibility of the Government to do it. This is my humble submission.

There is a need for redesigning the insurance scheme. I have already mentioned that. The Ministry of Agriculture should prepare an agriculture insurance scheme for the small and marginal farmers. I do not know when it will come. I would bring to the notice of the Government, in particular the Ministry of Agriculture, that there is harassment throughout the country as far as the recovery of money from the small and marginal farmers are concerned. So, I would appeal to the Government that they should not be harassed and they should not be arrested, nor their properties should be confiscated for the purpose of recovery. This message should go to the country.

Then, I come to the suicide of farmers. Everybody is aware of it. I am not making a political speech. The Government of Maharashtra has studied through the Institute called Indira Gandhi Agriculture Development and Research Institute and it has studied this issue. I have the figures with me. For one Starred and Unstarred Question, the hon. Minister has mentioned about the reasons and about the packages given by various State Governments. Some State Governments, like the State Government of Maharashtra, had announced a compensation of Rs. 1 lakh in the package and some other State Governments had announced a compensation of Rs. 50,000. But the point is, should the farmers commit suicide to get the benefit? It is a very sad state of affairs, that too after about 55 years of Independence. So, my humble submission is that सिर्फ कर्जा देने से किसानों की दशा में सुधार नहीं होगा। किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कमी कहां है?

There are a lot of moneylenders. Shrimati Indira Gandhi once announced that there will not be any repayment to moneylenders. The Government should make such announcements once and for all because private moneylenders are exploiting. Their interest rate is around 40 or 60 per cent. When I visited to enquire about the suicide of a farmer, I found that the interest was 96 per cent. They had taken Rs. 44,000

for their daughter's marriage. But after five years of her marriage, he committed suicide. So, the issue of moneylender is a major concern.

In Maharashtra, cotton area is a very sensitive area for suicide. Why? It is because for the last ten years we are importing cotton heavily. We are lowering our tariff every year. There is no buyer for cotton. There may be monopoly procurement by the Government of Maharashtra. But there is loss. These are some issues which we must address. See their economic condition. They get only farm loans. But what about their education expenses, health expenses and marriage expenses and other expenses? You are only restructuring the loan. What is meant by restructuring? इसका मतलब यह है कि हम आज मुर्दा बनने वाले थे, अब कल बनेंगे। So, restructuring is not the issue.

I want that Debt Relief Fund should be created. It will give a good relief. For the corporate sector we waive off the loans because the banks are capable. The design of cooperative banks is such that they cannot waive off the money. The only loan that they give is agriculture loan. There is no cross subsidy and commercial loan borrowing. So, I am appealing to the Government on two issues. Our cooperative banks may be allowed multiple activities so that they can sustain and their commercial strength can be increased. I am appealing and suggesting to the Government and in particular to the hon. Minister, Shri Sharad Pawar that he should appoint a Task Force and create one business model for the cooperatives. It is because its design is such that it cannot go for IPO or for commercial borrowing internally or globally[r44].

Unfortunately, the Government has taxed the cooperative banks. One 80(P) was an exemption. So, I am requesting through you and through the House that the Government should withdraw this income tax and 80(P) should continue. If the Government wants to raise something, it can create a business model. You can postpone it for 2 or 3 years till the Task Force submits a report. In all the banking systems, only tax is excluded. Already, all the co-operative banks are on oxygen. All the cooperative banks, the State cooperative banks, are on oxygen. They are on a dying bed. You say that they will not be taxed. But what about the revival? Okay, the Vaidyanathan Committee is there as far as long term and short term are concerned. But without changing the design, they are difficlt to sustain.

The same is the case with Agriculture insurance, the National Agriculture Insurance. It is the single insurance. No company will survive with a single business. They must have been allowed all agriculture related insurance like horticulture or, maybe, animal husbandry or fisheries etc. So, all these issues should be addressed. As regards the national agriculture insurance, comprehensive insurance, is a must. The multiple insurance, there should be multi-discipline.

At the same time, allow the technical transfer technology. It is also required for that. Without that, the increase in production per hectare will not be there. But the cost of production will be more. As on today, 157 per cent is the cost of production and as against this, realization is hardly 51 per cent. How the farmers will survive?

MR. CHAIRMAN : Please conclude.'

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : चेयरमैन महोदय, इसीलिए वे सुसाइड कर रहे हैं। उन्हें जिन्दा रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक-दो समस्याओं के बारे में और कहना चाहता हूं। हमारी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, उसके अन्तर्गत केवल 4 प्रतिशत किसान लाए गए हैं। इससे क्या होगा ? 51 प्रतिशत किसानों को पता ही नहीं है कि क्रॉप इंश्योरेंस क्या है। जब लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो वे इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे ? किसान के स्वीकृत ऋण में से कब आप इंश्योरेंस की प्रीमियम ऋण से काट लेते हैं उसे यह भी पता नहीं चलता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहूंगा that some training is required. I would request not to go for multi dynamic insurance like the tractor insurance, horticulture insurance. When you appoint evaluator for the rest of the areas, then why do you not go for the evaluator for crop cutting, etc.? एक साल के बाद किसान को पैसा मिलता है। एक साल के बाद वह क्या करेगा? He should get it within time, that is, two or three months. There should a time limit to get the crop insurance amount for that particular farmer.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Sir, I would request you to please allow me a few minutes. I have not spoken for the last one and a half year.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 20 minutes.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Only today I have spoken from my party. I have not wasted a single minute in the House. Please bear with me for some time.… (*Interruptions*)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आप किसानों की समस्या किसान की भाा में बोलिए। जिस भाा में आप बोल रहे हैं, उस भाा को किसान समझ नहीं रहा होगा कि आप उसके लिए क्या बोल रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : मैं किसानों की भाा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You need not answer Shri Mohanji.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): If you do not allow me to speak, then I have no hesitation in sitting down also.

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कितने परसेंट किसान, किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर पा रहे हैं। देश में केवल एक प्र ातिशत किसान हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। किसानों को सिर्फ क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया है। जब क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो खाली देने से क्या होगा।

महोदय, हमने कल भी, प्रधान मंत्री जी को लिखकर दिया है। अभी हमें केवल 42 के करीब संस्था का क्रेडिट रहा है। Sir, 42 per cent is for institutional credit only and 58 per cent is from the non-institutional credit. What does this non-institutional credit mean? It is moneylenders. In this 42 per cent, Gujarat, Maharashtra and Karnataka hold more than 55 per cent. In Maharashtra, it is 61 per cent just because of cooperative. But during the last two years, the cooperatives are also declining due to drought and defaulters. Now, what about the drought? What are the packages? The Government should think of some packages. सरकार की ओर से किसानों को पैसे देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, वह ठीक नहीं है। सरकार किसानों को अछूत समझती है। माफ कीजिए, किसानों को अछूत नहीं समझना चाहिए। इसके लिए सरकार को बजट रखना पड़ेगा और हस्तक्षेप करना पड़ेगा और किसानों को पैसा देना पड़ेगा। किसानों की 4 प्रतिशत ग्रोथ होने के बाद ही हमारी ग्रोथ रेट 10% बढ़ेगी।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Please bear with me two-three minutes. अभी हमारी 8 प्रतिशत ग्रोथ रेट जिसमें कृषि की सिर्फ 2 प्रतिशत ग्रोथ रेट है[rpm45]।

हमारी अभी 10 परसेंट ग्रोथ रेट ज्यादा कृषि उपज नहीं होने के कारण है , जबकि अभी कृषि उपज में 64 परसेंट तो हमारा एम्पलायमेंट है और खाली 22 परसेंट जी.डी.पी. में हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग में खाली चार परसेंट लोग मैन्युफैक्चरिंग में एम्पलायड हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are nine speakers from your party.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I know of it. They asked me to speak. Of course, some Members from Maharashtra may sacrifice their time. I do agree with you about time constraint.

MR. CHAIRMAN: If you do not conclude, shall I cut short the time of your allies? So, please conclude.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I do agree with you. Sir, you are talking about coconut. What is the situation regarding coconut? What about spices and coffee? How is their business now? कोकोनट के बारे में आज क्या हालत है, आप जानते हैं। हम उसका इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो हमारी एक ऐसी नीति हो...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I know that it is such a subject that you cannot conclude it so quickly. However, I would request you to conclude.

श्री बालासाहिब विखे पाटील : आखिरी एक विनती मैं यह कर रहा हूं कि हम हमेशा यह कहते हैं कि इतनी उपज हुई है। मंत्री जी, हमें उपज से कोई लेना-देना नहीं है, हमको यह चाहिए कि किसान की कितनी तरक्की हुई। अगले बजट में या रिपोर्ट में यह हो जाये कि खेती की तरक्की के साथ किसान की तरक्की कितनी हुई। किसान की तरक्की नहीं हो रही है और देश की तरक्की हो रही है। परिणाम 139 जिलों में नक्सलाइट्स आ गये हैं और It is spreading like a wild fire. हवा जैसे फैल रहे हैं, क्यों? किसान के बेटे, खेत मजदूर के बेटे उसमें हैं। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please conclude now so that I can call the next speaker.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I do agree with you. Within a minute, I am concluding. I do respect you very much. सभी एक तरह से हाथी जैसा हो रहा है, जो भी हम देखेंगे, उसमें कुछ न कुछ हमको मिलता है। सरकार कुछ कर रही है, यह हम मानते हैं। My point is this. I must tell something about the sugar package. The sugar package is a good package which the Government has given. But there is need to improve it further. Some negative networth are there. The affected units gave me this. Some good things are already there. But like a corporate sector, they are also very much sad. उसी हिसाब से किसान को कुछ न कुछ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to conclude now.

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं एक मिनट में बता रहा हूं। मेरे जिले में 45 गांव ऐसे हैं, जिनमें पिछले 20 साल से उनकी आमदनी 25 पैसे से कम है, वे कैसे जीते होंगे। जितने चितली गांव है, साहब चितली को जानते हैं, आठगांव, गोमलगांव करके गांव है, साहब उस गांव को भी जानते हैं। हमारे जिले में 600 गांव ऐसे हैं कि 10 साल से ज्यादा उनकी आमदनी 50 पैसे से कम है तो लोग कैसे जीते होंगे। लेकिन बात यह है कि उनका माइग्रेशन हो रहा है, लोग एजीटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन एजीटेशन करने के लिए वे लाचार हैं, क्योंकि वे मजदूरी कर रहे हैं, किसान नहीं रहे हैं। वे तो खेत मजदूर भी नहीं रहे हैं। वे इतने लाचार हैं कि कहीं भी जाकर कुछ भी काम कर लेते हैं।

इसलिए इसमें मुझे आपसे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके यू.पी.ए. गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन से भी मैंने बात की, उनका भी कहना है कि किसान के लिए सब लोग अच्छी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा निकलना चाहिए।

मैं दोबारा अच्छे काम के लिए, जो शुगर पैकेज दिया और कोआपरेटिव के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि दी, कम सूद का ऋण देने का प्रोवीजन किया, लेकिन इसके अलावा जो व्यवहार पीड़ित हैं, रैनफेड एथॉरिटी, इन्श्योरेंस में सुधार और डेब्ट रिलीफ फंड की हमें तुरन्त जरूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। डेट रिलीफ फंड से सूखे इलाकों के किसानों को रिलीफ जैसे ब्याज पूरा माफ करना जरूरी है। जैसे कार्पोरेट सेक्टर में वेवर होता है वैसे ही किसानों को भी डेब्ट रिलीफ फंड बनाने से लाभ मिलेगा।

इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ जवाब दें, बजट का भी मैं समर्थन करता हूं और जो कुछ बातें मैंने कहीं, निजी तौर पर भी कहीं कि इस बजट में कई कमियां हैं तो उनका उत्तर देने की कोशिश करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान में भयंकर वर्ा, ओलावृटि के कारण से लगभग 2 अरब धनराशि का नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं, जों, चना, मसूर की खड़ी खेती बरबाद हो गयी है। राजस्थान में पड़ी खेती भी बरबाद हो गयी है और उनका मूल्य कम हो गया है। कृाि बीमा योजना में सम्पूर्ण गांव को नुकसान ही इकाइ नहीं माना गया है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक टीम भेजकर नुकसान का आंकलन लगाकर किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाये। राज्य सरकार भी अपने साधनों से मदद कर रही है, परन्तु राज्य सरकार की धन की सीमा है।

कुओं पर शीघ्र विद्युत कनैक्शन दिया जाये। किसानों को सस्ते दर पर बैंकों से बिना भेदभाव किए कर्जा मिले और उसकी रेट भी स्स्ती हो। वर्ा का जल खेती के लिए बचाया जाये। खेत में एक पोंड बनाया जाये, इसमें सरकार मदद करे जिससे वर्ा का पानी एकत्रित किया जा सके।

सरसों की खरीद के भाव तय किये जाये और खरीदने के लिए केन्द्र बनाये जायें। आज तक यह व्यवस्था और भाव तय नहीं हुए हैं। किसानों को 8 घंटे की विद्युत पूर्ति की जाये। इस विद्युत पूर्ति के लिए पड़ौसी राज्यों से राजस्थान को विद्युत दिलवायी जाये। खेती के लिए ड्रिप सिस्टम को बढ़ाया जाये और इसके लिए अनुदान राशि बढ़ायी जाये। किसानों को समय पर अच्छे बीज और रसद उपलब्ध कराया जाये।

---

* The speech was laid on the Table.

SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, while supporting the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture for the year 2006-07, I would like to make certain points. I would request the hon. Minister to reply to those points at the time of his summing up.

I would like to say that this Budget has failed to address many vital problems faced by the common man, particularly the peasantry and the unemployed people[R46]. It is inadequate to meet the goals outlined in the National Common Minimum Programme. Sir, the reduction in the short-term interest rate for farmers and the proposed increase in the farm credit are welcome measures. But, these are limited in relation to the magnitude of the problems. Most of the recommendations of National Commission for Farmers have been ignored.

14.15 hrs. (Shri Balasaheb Vikhe Patil *in the Chair*)

Allocations have been reduced for food subsidy instead of extending coverage of the Public Distribution System in the context of the growing number of hunger deaths across the country. There is no concrete proposal to put an end to farmers' suicide and unemployment. There is no creation of a price stabilization fund for agricultural commodities and extension of crop insurance to all farmers and crops. As regards the outlook for agriculture, the economic survey for 2005-06 says that the prospects for the year look reasonably bright because of the good monsoon. But, it also draws attention to the fact that in order to exploit high potential for growth in emerging areas such as horticulture, floriculture, organic farming, genetic engineering and food processing among others, the development of rural infrastructure, rural extension service and agro-based and food processing industries is essential. Sir, as you know that more than 70 per cent of our people in India are rural based. They mainly meet up their livelihood to some extent by engaging themselves in producing various types of agri-horticultural products and other items in their respective villages.

Sir, in the age of liberalisation, privatisation and globalisation, we are getting continuous threats of the capitalist countries. They want to grab the entire global market by their products and their target is always the countries like us. They are doing it for their survival. For our survival, we will have to utilize the huge manpower available in our country. The soil condition and the climatic condition is very much favourable to produce various types of products, which are conforming to the international standards and it is a job oriented sector. For the last three years, we are regularly sending different floriculture products in the global market from West Bengal and from other States also it is being sent. But, we do not have the buffer infrastructure. Hon. Minister knows it that to have the cool chain is the primary condition for doing the floriculture business. We need to have a number of multipurpose cold storages throughout the country for the interest of lakhs and lakhs of growers who are producing it but cannot preserve it due to non-availability of the infrastructure. The items are perishable. So, if we do not preserve it in cold storage, then it is simply spoiled otherwise. It is learnt that out of the total production, 70 per cent is being wasted due to non-availability of the required infrastructure. So, I would urge upon the Government to please consider this issue seriously. Now, Sir, our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji is correctly saying that we should give priority in exporting agricultural products. But, how will we do it? Where is the infrastructure? While sending potatoes from West Bengal to different Asian countries, we have to import refrigerated containers from Germany. It is really a shame for us. Even after 58 years of independence, we do not have the refrigerated containers in our country. On several occasions earlier, I have met hon. Agriculture Minister and also met our Commerce Minister. They are aware of the fact and I am thankful to our hon. Minister that he has taken keen interest to resolve this issue[a47].

Sir, when we are sending our vegetables or potatoes or flowers or fruits, our experience is that all the giant countries like America, Australia, Holland etc. are providing transport assistance to all their growers. In our country also, the matter was referred to our hon. Agriculture Minister and in the case of potato he was kind enough to sanction transport assistance to compete with these giant suppliers. But the transport assistance was given for only one year which is going to end by 31st March.

Sir, what is our experience? Our experience is that our potato is the best in the world. Earlier, countries like America, Australia, Holland etc. used to supply it to other countries. Still they are supplying it, but when the buyers get our potato, they say that it is the best in the world. So, I would request the hon. Minister that the transport assistance which has been provided to potato growers, as an innovative scheme, under macro mode account, from the fund allocated to the State Governments, should be continued. Since we have started getting bulk orders, we need to have the support from the Central Government. So, I would request the hon. Minister to extend the transport assistance at least for another two years. We are confident that, if it is extended for another two years, by that time we would be in a position to establish our potato in the global market in such a way that we can compete with any country with our produce. The same is the case with flowers.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister another problem associated with the storage facility for potato. Potato is a one-time crop. The growers want to store potato in cold storage immediately

after getting their crop. The banks are providing financial assistance for this and a rate has been fixed for this which is Rs. 161 per 50 kg. whereas the market price is Rs. 230 per 50 kg. I had a talk with different bank authorities. They are saying that they cannot increase it since the Government has fixed the rate. But to ensure supplies and to ensure preservation of large quantity of potatoes for export and also for domestic use, I think, the hon. Minister should take up the matter with the bank authorities and see that the farmers get more credit from banks and he should also see that the rate is enhanced from Rs. 161 per 50 kg. which was fixed long back. I think it should be fixed at Rs. 240 per 50 kg. Then only the growers will get some benefit.

As far as fruits are concerned, we are grateful to our hon. Minister that last year, for the first time, he organised an Indian Mango Fair at Singapore and the response was very good. We are very much encourage by this and we are hopeful that we would be in a position to export substantial quantity of mangoes and other fruits to different countries.

Sir, what is the need of the hour? The need of the hour is that the Government should build infrastructure for proper storage of our fruits and the Government should also extend support for export. We are supplying 28 varieties of vegetables to different countries. But our experience is that there are some anomalies in air freight. Though this is not the concern of the hon. Agriculture Minister, I would request that these anomalies should be removed to help our farmers who want to export these vegetables.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI SUDHANGSHU SEAL : I will conclude.

I would like to submit that export of agricultural products would be successful in our country only if we are equipped with international standard packaging. In packaging, we are lagging behind other countries. The Government should take an initiative to improve packaging. There should be a unit in all the States and we should have foreign expertise so that our growers and entrepreneurs can have international standard export packaging system. The Government should extend support to them so that whatever end product is sent to different countries, it conforms to international standard[k48].

Lastly[r49], I would like to draw the attention of the hon. Minister that there is huge potentiality in terms of supplying vegetables, fruits, potatoes and other items. But what we find is that we do not have sufficient cold-storage facilities and we do not have sufficient infrastructure. So, I believe the hon. Minister will look into this as it would ultimately help lakhs and lakhs of growers in India.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, कृषि विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बात सभी लोग जानते हैं और आपने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि देश के सत्तर फीसदी से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं और लगभग 63 प्रतिशत लोगों को रोजगार खेती या उससे जुड़े हुए उद्योगों से मिलता है। इसके बावजूद खेती और किसानों की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया जाता। हालांकि इस बार जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो अगले ही दिन हिन्दुस्तान भर के अखबारों में यह कहा गया कि किसान पर धन की वर्षा हुई है। लेकिन असलियत क्या है कि एलोकेशन बढ़ने के बाद भी पिछले साल की तुलना में टोटल प्लान बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोआपरेशन का हिस्सा 1.98 प्रतिशत जो पिछले वर्ष था, वह घटकर 1.89 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन तथा आईसीएआर में पिछले वर्ष .54 प्रतिशत था जो घटकर इस वर्ष .53 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हस्बैंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज में पिछले वर्ष .31 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष .30 प्रतिशत रह गया है। यह शब्दों की बाजीगरी से काम नहीं चल सकता। यथार्थ में किसान को क्या मिल रहा है, इसकी तरफ जाना होगा।

यह जोर दिया जाता रहा है कि किसानों को क्रेडिट फ्लो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो ऋण है, यह ऋण ही किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। इस बार शॉर्ट टर्म लोन की इंटरेस्ट रेट भले ही 7 प्रतिशत कर दी गई है लेकिन हम लोगों ने फील्ड में जाकर देखा है और लोगों से बात की थी कि पिछले वर्ष तक 9 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक दर रखी गई है और उस पर कम्पाउंड इंटरेस्ट लगता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ज किसान दे नहीं पाता है और जब वह गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो उसके ले जाने का, उसके खाने-पीने का सबको किसान के साथ ही जोड़ दिया जाता है।

अगर कोई अपराधी जेल भेजा जाता है तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर किसी किसान को पकड़ कर जेल ले जाया जाता है तो उसको पकड़ने और ले जाने के लिए प्रयोग की गयी गाड़ी में लगने वाले पेट्रोल या डीजल का खर्च, खाने-पीने का खर्च, सब कुछ जोड़ कर किसान से वसूल किया जाता है। इसकी वजह से किसानों के सामने एक बड़ा संकट रहता है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में भी एक कानून बना था कि अगर कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी जमीन की नीलामी नहीं होगी। जिससे किसान को रोजी-रोटी मिलती है, अगर वही नीलाम हो जाएगी तो वह कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए यह मेरा सुझाव और मांग है कि किसानों पर आप जो इन्ट्रेस्ट लगाते हैं, वह इन्ट्रेस्ट किन्ही भी परिस्थितियों में मूल धन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वह 10,000 रूपए ऋण लेता है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है तो उस पर ब्याज की अधिकतम सीमा इस मूल धन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी मांग लोग लगातार करते आ रहे हैं।

महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां जो जमीन है, जिस पर बुआई होती है, वह लगभग 17.3 मिलियन हेक्टेअर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 46 प्रतिशत है। साथ ही 23 मिलियन हेक्टेअर जमीन ऐसी है जिस पर कुछ भी नहीं होता है, वह बंजर है। जिस जमीन पर बुआई होती है उसका भी मात्र एक-तिहाई हिस्सा सिंचित है और शेा दो-तिहाई हिस्सा असिंचित है। इसलिए अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए कोई योजना चलाई जाए तो हम न केवल आत्मनिर्भर हो सकेंगे बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न दे सकते हैं और खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए "भूमि सेना" नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उस भूमि के सुधार पर जितना भी खर्च आता है, जो भी इनपुट उस भूमि को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, वह सब सरकार देती है। जिस व्यक्ति को वह भूमि एलॉट की जाती है, वह उस पर काम करता है और काम करने के बदले में उसे 60 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। जब वह भूमि खेती योग्य हो जाती है तो उस काम करने वाले व्यक्ति को ही वह जमीन दे दी जाती है। अगर इस तरह का कोई इन्सेंटिव किसानों के लिए हो तो देश में जो बड़े पैमाने पर बंजर जमीन पड़ी है, उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है और किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।

14.33 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी इसके तहत ब्लॉक को एक यूनिट माना गया है। इसे गांव स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है वरना इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। अभी ललितपुर में एक जगह पर दो ब्लॉक्स के आधे-आधे हिस्सों में फसल पूरी तरह नट हो गयी। लेकिन जब तक

पूरे ब्लॉक की फसल नट न हो गयी हो, किसानों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए इस स्कीम को गांव स्तर तक लाने की आवश्यकता है।

जहां तक आईसीएआर अथवा डीएआरई का मामला है, यह आपका एक ऐसा विभाग है कि अगर इसको ठीक तरीके से मदद पहुंचाई जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कई फसलों में हमारे आस-पास के देशों में प्रति हेक्टेअर उत्पादन हमसे ज्यादा है। अगर रिसर्च का पर्याप्त मौका मिले तो हम उपयोगी सीड्स और दवाइयां तैयार कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में भी एलोकेशन जितना होना चाहिए, उतना नहीं cè[R50] ।दुनिया के दूसरे देशों में भी, हमारी बगल में श्रीलंका है, वहां पर भी और लैटिन अमेरिकन देशों तथा ि वकासशील देशों में भी इस क्षेत्र में हमारे से दो-तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। हमारे यहां बहुत कम हो रहा है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि आईसीएआर में बड़े पैमाने पर स्टाफ की कमी है और 1400 वैज्ञानिकों की पोस्ट्स खाली हैं। वैज्ञानिकों का काम वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, गैर-वैज्ञानिक नहीं कर सकता। अन्य विभागों में तो आप एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जा सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च का काम है, वह केवल साइंटिस्ट्स ही कर सकते हैं। जब इस बारे में पूछा जाता है तो हर बार यही बाधा आती है कि वित्त मंत्रालय अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि यह देश की तरक्की से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वित्त मंत्री जी को चाहिए कि यह जो पाबंदी है, new recruitment cannot be done. This bar should be removed in the Agriculture Department so far as ICAR is concerned because 1400 posts of scientists are lying vacant for the last so many years. I, as the Chairman of the Standing Committee on Agriculture, have been informed by the Officers of the Department … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Posts of scientists are exempted. They can recruit. … (*Interruptions*)

प्रो. राम गोपाल यादव : 1400 पोस्ट्स खाली हैं। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की पोस्ट्स पर एक्जम्प्शन है। Now, I would like to request the hon. Agriculture Minister, through you, Sir, to kindly look into it and see that these vacancies are filled up as soon as possible.

मैं आईसीएआर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हार्टिकल्चर वगैरह है, सुगंधित पुपों के बारे में मेरी विशेा रूप से राय है कि यह जो नई रिसर्च हो रही है, तमाम तरह के फूल और सुन्दर फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से खुशबू गायब हो रही है। बिना खुशबू के फूल का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रजनीगंधा इतना सुन्दर फूल है। लोग उसे लेकर आते हैं कि रजनीगंधा है, लेकिन शाम होते-होते उसकी खुशबू का पता नहीं लगता। मैंने नेशनल हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट से कहा कि आप इस तरह का शोध करें, जिससे फूलों में खुशबू बनी रहे, केवल देखने में ही फूल सुन्दर न हो। इसी तरह से गुलाब धीरे-धीरे बढ़िया आ रहा है, लेकिन खुशबू गायब हो रही है। इस तरह की रिसर्च का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। रिसर्च हो और उसमें इन सुगंधित पुपों की जो धीरे-धीरे सुगंध खत्म हो रही है, उसे बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

जहां तक एनिमल हसबैंड्री और डेयरिंग तथा फिशरीज का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है. हम जानते हैं कि खेती में एक सीमा से ज्यादा पैदा नहीं हो सकता। आप चाहे जितना अच्छा बीज लगाएं, चाहे जितनी अच्छी खाद दें, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा उसमें पैदा नहीं हो सकता। लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अपार सम्भावनाएं हैं। हालांकि इस वक्त भी दूध के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से और प्रोसेसिंग न होने से दिक्कतें आती हैं। हालांकि वह कृाि मंत्रालय से अलग विभाग हो गया है। लेकिन वह अभिन्न रूप से इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दो प्रतिशत से भी कम हमारे देश में प्रोसेसिंग हो पा रही है। इसलिए जो पैरिशेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, हालांकि सही आकलन नहीं हो पा रहा है, लेकिन विभिन्न सोर्सेज से पता चला है कि सालाना 50,000 करोड़ रुपए के करीब ये सब्जियां और फल प्रोसेसिंग के अभाव में सड़ जाते हैं। हर साल हमें इतना बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग विभाग है, उसे ज्यादा फंड का एलोकेशन करके कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है[R51]।

एक बात मैं दूध और मांस के बारे में कहना चाहता हूं। दूध और मांस से करीब-करीब उतना ही रैवेन्यू मिलता है जितना कि गेहूं, धान और गन्ना तीनों को मिलाकर रैवेन्यू मिलता है। इस पर भी ध्यान देने की जरुरत है। जो अमूल और मिल्क फूड है, इसकी मार्किट में रैपूटेशन है लेकिन दिल्ली मिल्क स्कीम का अब वह सम्मान मार्किट में नहीं है जो होना चाहिए। डीएमएस का जो हम दूध लेते हैं उसका स्वाद नहीं है

और उससे जो दही बनता है उसका स्वाद भी वैसा नहीं है जैसा दूसरे दूध से बनता है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो एनीमल हस्बैंडरी और डेयरी से संबंधित है। अभी हाल में बर्ड-फ्लू का प्रश्न बड़े पैमाने पर आया और बड़े पैमाने पर मुर्गियों की हत्या की गयी। माननीय मेनका जी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मुझे याद आता है तब से मुर्गियां जब भी मरती हैं तो एक साथ मरती हैं। यह जो हल्ला मचाया गया इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश की बू आती है। एक कंपनी रोा जो बर्ड-फ्लू की दवा टेमीफ्लू बनाती है उसका लगा कि सारे लोग उससे दवा खरीदें। जब से मुर्गियों को मारा जाने लगा था, हमने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया था। मैं सोच रहा था कि माननीय मेनका जी ने इस पर अपना बयान क्यों नहीं दिया?

श्रीमन्, आपने घंटी नहीं बजाई और मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा आपके घंटी बजाने से पहले ही अपनी बात समाप्त कर दी है, इसलिए लम्बी बात नहीं करुंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कृाि मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं वे उन पर अमल करेंगे। महोदय, किसान देश की रीढ़ हैं और अगर किसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो देश भी स्वस्थ नहीं रह सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI AVINASH RAI KHANNA (HOSHIARPUR):Sir, The farmers of India is in great pitiable position that he is thinking of leaving this profession. I would like to point out about the farmer of Nadala, district Kapurthala, Punjab who committed suicide while sitting in the grains market and because je could not sell his paddy for 7 consecutive days and ultimately resorted to this ultimate step. I request that the farmers may be rescued from such situations. Providing more loans to farmers is not going to solve the problem but they should be freed from this cycle of loans and interests. Today, farmers are facing a number of problems like loan, electricity, water shortage, fertilizer shortae, seed shortage, adulterated seed and pesticides, marketing problems, pricing problems and many more.

The other important point I would like to draw your attention to is towards the Forests Act which was passed about a century ago and then Punjab Preservation Land Act was passed in 1900, the same continues to this day without any change, and by application of its provisions and clauses the farmer is not able to use his land in a manner they would like to do. Neither they can cut the tree planted on their land. About 470 village of kandi area are facing this problem. If they are not allowed to use their land in a way they want, they should be given compensation.

When the price of the wheat and paddy is fixed, the farmers participation must be assured. The water level is going down. In the year 1955 the water level was 34.8 MAF(million acre feet) but today it is 12.5 MAF and the minimum requirement is 36.5 MAF. Therefore, special provision and budget provisions are required to be made to meet water shortage.

The farmers do not get proper price because of lack of proper marketing faculties to the farmer. I request that proper attention is required to be paid for suitable marketing facilities to the farmers.

* The speech was laid on the Table.

In Punjab there is acute power shortage, the farmers who have applied for connection are in the waiting lists since 1992-93. It is 14.15 years long wait which is another cause that is increasing the problems of the farmer. The government should make provisions in this budget in order that the water and eelectricity problems of the farmers could be reduced.

The green revolution has had been missed. We have to think it more seriously. Today the farmer is opting suicide a better way than to be a farmer.

In short the problem can only be solved if the government shows courage to implement schemes like Farmers Income Insurance Scheme. When the farmer will be confident about his income he will work more hard to meet the challenges. If once for all the government commits and takes a decision to make the farmer debt-free, it will solve the problem of the farmers.

The decision to import whet at by the government has created unrest among the farmers. The import wheat by the government has created unrest among the farmers. The imported wheat will reach the crop of India right at a time when the harvest of Indian farmers will also reach market. Is our farmer in a position to compete with the foreign farmers that too in our domestic market is a question that needs to be decided.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति जी, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। इस विषय पर चर्चा हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं। यह बात सही है कि यह देश कृषि प्रधान देश है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि से ही बहुसंख्यक आबादी को रोजगार मिलता है। महोदय, जिस देश की अधिकतम जनसंख्या खुशहाल न हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न cÉä[r52], मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। हम सभी लोग कहते है कि देश तरक्की कर रहा है। महोदय, जब भी कृषि पर चर्चा होती है, यह बात मेरे मन से नहीं जाती है, यहां पर बैठे हुए हम सभी माननीय सांसद लोग किसान का बहुमत वोट लेकर इस सदन में आए हैं और बड़ी अच्छी बात हम भी करते हैं और सरकार भी करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मगर किसान के हित के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए और नीतिगत फैसला होना चाहिए, वह देखने को नहीं मिलता। मैं स्वयं किसान हूं। मुझे खुशी हे कि इस देश के कृषि मंत्री पवार साहब भी जाने-माने किसान हैं और किसानों के हित चिंतक हैं। मगर अभी जो बजट आया, उस बजट के बारे में गोपाल बाबू ने ठीक कहा है। आपने कहा कि हम सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण देंगे। यह फैसला हम सभी लोगों को अच्छा लगा। किसानों के मन में भी यह बात गयी है, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, इसे आगे भविष्य में देखना है। सहकारिता विभाग भी इन्हीं का है। जो सूद नहीं लेता, सूद का सूद और सूद दर सूद और इतना सूद कि उसके लिए सारी जमीन बिक जाती है। गोपाल बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको जमीन का व्यावहारिक ज्ञान है। इस देश में ऐसा कौन सा कानून है, जिस कानून में अकेले किसान से जेल में उसके भोजन का पैसा वसूल किया जाता है। जेल में किसी और से, यहां तक कि देशद्रोही से

भी भोजन का पैसा नहीं वसूल किया जाता है, सिर्फ किसान से ही भोजन का पैसा वसूल किया जाता है। पूंजीपति इस देश का अरबों रूपया लेकर बैठे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं होता, उसके घर पर पुलिस बहुत देर से जाती है, लेकिन किसान का बेटा यदि एक हजार रूपए को-आपरेटिव या ब्लाक से कर्ज लेता है, यहां पर किसान क्रेडिट की बात हो रही है, तो उसके घर पर 31 तारीख बीतने के बाद एक तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। सौ रूपए और पचास रूपए पुलिस को घूस देते-देते उसका कर्ज भी नहीं सध पाता और वह कर्ज के बोझ से दबता जाता है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि इस देश का किसान इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि वह कर्ज का बोझ बरदाश्त नहीं कर सकता। कर्ज जरूरी है और आपको कर्ज देना भी चाहिए, लेकिन मात्र कर्ज दे देने से काम नहीं चलेगा। आप हर तरफ सोच रहे हैं, सोचते रहिए। खेत जोताई से लेकर, गुड़ाई से लेकर, सिंचाई से लेकर, बीज डालने से लेकर, फिर सिंचाई कर, खलिहान में फसल तैयार करने तक, जो किसान की लागत होती है, क्या वह सरकार को नहीं मालूम है? क्या सरकार उसे नहीं जानती है? क्या सरकार का अमला और पदाधिकारी इस चीज को नहीं जानते हैं? वे जानते हैं कि प्रति एकड़ जोताई कितना खर्च होता है? कितना बीज प्रति एकड़ लगता है? कितना खाद लगता है? क्या सिंचाई की व्यवस्था है? अगर सरकार सिंचाई की सुविधा नहीं दे रही है, तो किसान अपनी मेहनत से पंप-सेट लगाकर डीजल से इस काम को करता है। इसमें कितना खर्च होता है? जब सरकार सब जानती है, तो सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देती हैं? इस देश में एक नट बनाने वाली फैक्टरी का मालिक, स्वयं अपने सामान का दाम तय करता है, पान का दुकानदार अपने पान का दाम स्वयं तय करता है, मगर किसान जो अपने खून और पसीने से अनाज को पैदा करता है, उसको अपनी फसल का दाम तय करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे सरकार तय करती है। वह व्यापारी तय करता है। किसान का बेटा उसको तय नहीं कर सकता है। इस देश में यह कैसा कानून है? यह कैसी कृषि नीति है? राज्य सरकारों को तो पता ही नहीं और दिल्ली की सरकार भी कृषि नीति के मामले में फेल्योर है[c53]।

सिद्धान्त और नीतियां ठंडे कमरों में बन रही हैं और जमीन पर लागू नहीं हो रही हैं। महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो काम किया, ठीक बात है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि उसे जमीन पर भी लागू किया जाए। सरकार एक फैसला करे कि किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे किसानों की 80 प्रतिशत समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान कहते हैं कि जो खर्चा हो रहा है, उसे आप देखिए, उसके हिसाब से कीमत तय करिए तथा हमें लाभकारी मूल्य दीजिए। उससे हमारे बाल-बच्चे भी खाएंगे और व्यापारी लोग चाहे उसका दुगना बनाएं, हमें कुछ नहीं कहना है।

महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन किसान की फसल अभी खेत में है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम गेहूं आयात करेंगे। यह कौन